शाल एच. मुसलियार और ए. एन. आर.ईटीसी। ईटीसी।

/

वी.

केरल राज्य और ओ. आर. एस., ई. टी. सी. ईटीसी।

18 अगस्त, 1993

/

[एस. रत्नवेल पांडियान, एस. सी. अग्रवाल, एस. मोहन, बी. पी. जे. ई. वी. एन. रेड्डी और एस. पी. भरुचा, जे. जे.]

शिक्षा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया -

योग्यता मार्गदर्शक सिद्धांत होगा-कोटा वितरण-सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सीटें भरी जाएंगी-शेष 50 प्रतिशत सीटों को प्रबंधन-सी द्वारा भरा जाएगा-चयन सख्ती से योग्यता के आधार पर-निशुल्क सीटों के बीच समान वितरण और भुगतान seats-N.R.Is यदि कोई कुल सीटों के 5 प्रतिशत से अधिक की सीमा तक प्रवेश लेता है तो भुगतान सीटों से बाहर होगा-भर्ती किए गए छात्रों के पूर्ण विवरण वाले विवरण सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे-द्वारा सत्यापन पर केवल अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को लागू करने का आदेश

/

सरकार-मामलों के इन समूह में उत्पन्न होने वाले प्रश्न ों की सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ।वर्तमान रिट याचिकाओं में योजना की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठाया गया है

जे. पी. उन्नीकृष्णन बनाम में उच्चतम न्यायालय द्वारा विरचित किया गया।ए. पी. राज्य, [1993] 1 एस. सी. आर. 594 के साथ-साथ उक्त निर्णयों के अनुसरण में और उनके आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और आदेश की प्रयोज्यता।ई उन्नीकृष्णन में, उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (एम. ई. आई.) के बारे में कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया। हालांकि, कई राज्य सरकारों ने याचिकाकर्ता को नोटिस दिया कि उन्हें उक्त निर्णय का पालन करना होगा।याचिकाकर्ताओं में से कई संस्थानों ने आपत्ति जताई कि चूंकि वे एम. ई. आई. हैं, इसलिए उक्त निर्णय या उनके अनुसार बनाए गए नियम और आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं।संबंधित सरकारों ने विरोध को नजरअंदाज कर दिया और याचिकाकर्ताओं से उक्त निर्णय का पालन करने का आह्वान किया।याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाएं दायर कीं।1993 की रिट याचिका 350 और 355 में 14 मई, 1993 का एक अंतरिम आदेश याचिकाकर्ताओं की सहमति से निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया था।

/

(i) कुल सीटों का पचास प्रतिशत राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा/परीक्षा के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

(ii) शेष पचास प्रतिशत में प्रवेश विशेष धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित उम्मीदवारों के प्रवेश द्वारा विनियमित किया जाएगा।

649 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1993] एस. यू. पी.1 एस सी आर।

650

}

ए सख्ती से योग्यता के आधार पर।योग्यता का निर्धारण योग्यता परीक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है; या किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर जो संस्थान स्वयं आयोजित कर सकता है या चयन परीक्षा के परिणामों के प्रदर्शन के आधार पर जो राज्य सरकार राज्य में तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित कर सकती है। ऐसे चयनित उम्मीदवारों को ऐसी शर्तों का पालन करना होगा

/

ट्यूशन और अन्य शुल्क के भुगतान के मामले में जो राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाए।

(iii) यह आदेश इस धारणा पर दिया गया था कि याचिकाकर्ता अल्पसंख्यक संस्थान हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई सी स्थिति पर प्रश्न उठाने के लिए उत्तरदाताओं के लिए यह खुला था।

(iv) आदेश याचिकाकर्ताओं को रिट याचिकाओं में उठाई गई अन्य सभी दलीलों का आग्रह करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अंतरिम अंतर्वर्ती आदेश याचिकाकर्ताओं की सहमति पर और सभी डी दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया था।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया:1.1 .1993 की रिट याचिका 284 और 1993 की 350 में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

ई प्रवेश इस तरह से नहीं किए गए हैं, याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर अपने कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति है।प्रवेश पूरा करने के बाद याचिकाकर्ता पूर्ण समतुल्य प्रस्तुत करेंगे।

भर्ती किए गए छात्रों आदि का विवरण सक्षम प्राधिकारी को।इसमें दिए गए निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि उपरोक्त आदेश उनके अभ्यावेदन के आधार पर और जवाबी शपथपत्र दायर करने से पहले भी दिए गए हैं।[657 - ए, बी, ई] 1.2।अन्य सभी मामलों में, विशेष रूप से उल्लिखित मामलों को छोड़कर

इसके बाद, न्यायालय द्वारा 14 मई, 1993 को डब्ल्यू. पी. 355 और 1993 के 350 में दिया गया आदेश निम्नलिखित संशोधनों के साथ आदेश होगा (जो

/

संशोधन 1993 के डब्ल्यू. पी. 350 और 355 में भी लागू होंगे)।[657 - च) (क) पैरा (3) की निरंतरता में यह और स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी संस्थान एम. ई. आई. है या नहीं, यह सरकार को सत्यापित करना और निर्धारित करना है।यह आदेश ईमानदारी से उन संस्थानों पर लागू किया जाएगा जो एस. एच. मुसलियार बनाम द्वारा सत्यापन पर M.E.Is पाए जाते हैं।

केरल राज्य

651

सरकार ने।[657 - जी-एच]

/

(ख) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों द्वारा 50 प्रतिशत सीटें भरी जाएंगी।

परीक्षा के साथ-साथ योग्यता के आधार पर प्रबंधन द्वारा भरी जाने वाली शेष 50 प्रतिशत सीटों को निशुल्क बी सीटों और भुगतान सीटों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।N.R.Is., यदि कोई कुछ हद तक स्वीकार नहीं किया गया है

कुल सीटों के 5 प्रतिशत से अधिक योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले भुगतान सीटों में से होंगे।[658 - ए-बी]

(ग) प्रवेश पूरा करने के बाद प्रत्येक कॉलेज सक्षम प्राधिकारी को सी में भर्ती छात्रों का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा।[658 - सी]

1.3 .14 मई, 1993 का आदेश डब्ल्यू. पी. में संबंधित संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
497/93,597/93,442/93,525/93,392/93 क्योंकि न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं है कि उन्हें M.E.Is के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

/

[658 - ई-एफ] 1.4।डब्ल्यू. पी. 598/93 में एक निश्चित समझौता किया गया है

संस्थान और केरल सरकार के बीच, जिसके अनुसार 85 प्रतिशत सीटें सरकार द्वारा भरी जानी थीं, शेष 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन को अपने विवेक से भरने के लिए छोड़ दी गई थीं।ई चूंकि मूल सिद्धांत यह है कि प्रवेश के मामले में योग्यता मार्गदर्शक सिद्धांत होगा, इसलिए विवेकाधीन कोटा के लिए याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है।उक्त रिट याचिका उपरोक्त संशोधनों के साथ 14 मई, 1993 के आदेश द्वारा शासित होगी।[658 - एच; 659-ए-बी]

/

1.5 .एक बड़ी पीठ को इन मामलों के समूह में उत्पन्न होने वाले प्रश्न की सुनवाई करनी चाहिए।[653 - एच]

मौलिक न्यायनिर्णय:1993 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 598।भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत

/

सह

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या।536/93 , 597/93 , 407/93 , 343/93 , 613/93 , 399/93 , 626 27/93 , 284/93 , 327/93 , 350/93 , 355/93 , 482/93 , 484/93 , 485/93 , 474/93 , 523/93 , 417/93 , 444/93 , 317/93 , 442/93 , 525/93 , 463/93 , 469/93 और 392/93।

एच. सुप्रीम न्यायालय रिपोर्ट [1993] एस. पी.1 एस सी आर।

652

याचिकाकर्ताओं के लिए ई. एम. एस. इनाम।

/

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

योजना की प्रयोज्यता पर सवाल उठाने वाली कई रिट याचिकाएं

इस न्यायालय विरचित जे. पी. उन्नीकृष्णन बनाम.आंध्र प्रदेश राज्य, [1993] बी 1 एस. सी. आर 594 के साथ-साथ उक्त निर्णय के अनुसरण में और उसके आधार पर कई राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों की प्रयोज्यता भी हमारे सामने रखी गई है।कुछ रिट याचिकाओं में नियम निसी पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य नए मामले हैं।हमने सीरियटम में हमारे सामने रखी गई प्रत्येक रिट याचिका को लिया है और संबंधित वकील को सुना है।

/

उन्नीकृष्णन में, हमने इसके बारे में कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (M.E.Is.)।वास्तव में एम. ई. आई. से संबंधित कुछ मामलों को अलग से सुनवाई के लिए उस बैच से अलग कर दिया गया था।चाहे जो भी हो, कई राज्य सरकारों ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं कि उन्हें उक्त निर्णय और उसके अनुसार बनाए गए नियमों और आदेशों का पालन करना होगा।कई याचिकाकर्ताओं-संस्थानों ने आपत्ति जताई कि चूंकि वे एम. ई. आई. हैं, इसलिए उक्त निर्णय या उनके अनुसार बनाए गए नियम और आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं। संबंधित सरकारों ने उक्त दावे को नजरअंदाज कर दिया और याचिकाकर्ताओं से उक्त निर्णय, नियमों और आदेशों का पालन करने का आह्वान किया।यह है।

/

तब याचिकाकर्ताओं ने इन रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

हमारे समक्ष रखी गई कुछ रिट याचिकाएं एक पीठ के समक्ष आई थीं, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश शामिल थे।

एफ यूएस (बी. पी. जीवन रेड्डी, जे.) 14 मई, 1993 को।1993 की रिट याचिका 350 और 355 में याचिकाकर्ताओं के वकील ने निम्नलिखित आदेश पर सहमति व्यक्त की और तदनुसार यह किया गया:

" याचिका सं. लिखें।350 और 1993 का 355

हमने श्री सोली जे. सोराबजी को सुना है, जिनके लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं

/

इन दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता।नियम जारी करें।

2. निम्नलिखित शर्तों में एक अंतरिम आदेश होगाः

i) याचिकाकर्ताओं के शैक्षणिक संस्थानों में कुल प्रवेश का पचास प्रतिशत उम्मीदवारों द्वारा भरने की अनुमति दी जाएगी।

एच. एस. एच. मुसलियार बनामकेरल राज्य

653

राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा/परीक्षा के आधार पर चयन किया जाता है।इस प्रकार चुने गए और छात्रों के इस वर्ग में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(ii) शेष पचास प्रतिशत को याचिकाकर्ताओं द्वारा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए विनियमित किया जा सकता है।हालांकि, चयन संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच योग्यता के आधार पर सख्ती से किया जाएगा।ऐसी योग्यता का निर्धारण योग्यता परीक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा; या किसी भी उद्देश्य सी परीक्षा के आधार पर जिसे संस्थान स्वयं ऐसे सापेक्ष और प्रतिस्पर्धी गुणों को निर्धारित करने के लिए आवेदन कर सकता है; या चयन परीक्षाओं के परिणामों के प्रदर्शन के आधार पर जो राज्य सरकार स्वयं राज्य में तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित करती है।याचिकाकर्ताओं के लिए यह वैकल्पिक है कि वे इन तीन तरीकों में से किसी एक को अपनाएँ और इसे समान रूप से लागू करें।के बीच योग्यता के आधार पर इस तरह से चुना जा सकता है

हालाँकि, अल्पसंख्यक शिक्षण और अन्य शुल्क के भुगतान के मामले में ऐसी शर्त का पालन करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

/

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश इस धारणा पर दिया गया है कि याचिकाकर्ता अल्पसंख्यक संस्थान हैं।याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई इस स्थिति पर प्रश्न उठाने के लिए यह जवाब देने के लिए खुला है।

4. हालाँकि, यह आदेश याचिकाकर्ताओं को रिट-याचिकाओं में उठाए गए अन्य सभी तर्कों का आग्रह करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वास्तव में, यह अंतरिम अंतर्वर्ती आदेश मध्यस्थों की सहमति पर किया गया है।

याचिकाकर्ता और सभी दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना।1993 की रिट याचिका संख्या 360

/

इस याचिका को मामलों के इस समूह से अलग करें और इसे सामान्य क्रम में सूचीबद्ध करें।

हालाँकि, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील उपरोक्त आदेश से सहमत नहीं थे, जिसके बाद उन्हें एक स्वामित्व वाली पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया था।बाद में यह आदेश दिया गया कि ऐसी सभी रिट याचिकाओं को एच 654 होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1993] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. ए. की सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जाए जिसने उन्नीकृष्णन पर फैसला सुनाया था।

हमारे समक्ष रखी गई रिट याचिकाओं को पाँच में वर्गीकृत किया जा सकता है।

रिट याचिकाओं में कथन के अनुसार श्रेणियां।, (1) गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, (2) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

जो सहायता के रूप में राज्य निधि की प्राप्ति में हैं, (3) बी के संबंध में जो रिट याचिकाओं में दिए गए कथनों से स्पष्ट नहीं है कि वे सहायता प्राप्त हैं या गैर-सहायता प्राप्त संस्थान, (4) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दायर उन्नीकृष्णन के सही निहितार्थ और प्रयोज्यता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं।

जो M.E.Is होने का दावा नहीं करते हैं, (5) रिट याचिकाएं जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं।

एस.

पहली श्रेणी में रिट याचिकाओं की संख्या।284 1993 का कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन, बैंगलोर और अन्य।वी.कर्नाटक राज्य और अन्न।, 317 1993 का डॉ. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी.कर्नाटक राज्य और अन्य।, 327 1993 का मदरसा-ई-मदीनाथुल उलूम ट्रस्ट और अन्न।वी.कर्नाटक राज्य और अन्य।, 350 1993 का इस्लामी

/

शिक्षा अकादमी, मैंगलोर और अन्य।वी.कर्नाटक राज्य और अन्य।, 482 1993 का क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन, वेल्लोर, तमिलनाडु बनाम।तमिलनाडु राज्य, 1993 का 613 सोमैया विद्या विहार बनाम।महाराष्ट्र राज्य और 1993 का 627 हैदराबाद (सिंध) राष्ट्रीय कॉलेजिएट बोर्ड और अन्य।वी.महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

/

दूसरी श्रेणी में दो रिट याचिकाएं शामिल हैं; (1) डब्ल्यू. पी.

536 1993 का माराथानासियस कॉलेज बनाम।केरल राज्य, और (2) 1993 का डब्ल्यू. पी. 598 सहल एच. मुसलियार और अन्न।वी.केरल राज्य और अन्य।

तीसरी श्रेणी में रिट याचिका-संख्या शामिल है।444/93 विजयनगर

/

एजुकेशन ट्रस्ट (रेग.) और ए. एन. आर.वी.कर्नाटक राज्य और अन्न।, 417 1993 के फा. मुलर के धर्मार्थ संस्थान और अन्य। वी.कर्नाटक राज्य और अन्य।, 523 1993 का श्री नानक थिरा साहेब और अन्न।वी.कर्नाटक राज्य और अन्न।, 474 1993 ऑल इंडिया इस्लामिक फाउंडेशन और ए. एन. आर.वी.तकनीकी निदेशक

शिक्षा और एन. आर., 485 1993 का अल-बदर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम।जी कर्नाटक राज्य, 1993 का 484 खाजा एजुकेशन सोसाइटी बनाम।कर नाटक राज्य, 1993 का 355 एस. वेंकटेश एजुकेशन सोसाइटी और अन्न।वी.कर्नाटक राज्य और अन्य।, 429 1993 का राजा राजेश्वरी डेंटल कॉलेज बनाम।कर्नाटक राज्य और अन्न।, 479 1993 का तमिलनाडु तकनीकी शैक्षिक प्रतिष्ठान v.तमिलनाडु राज्य और अन्न।, 597 1993 का मुस्लिम शैक्षिक

एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया बनामतमिलनाडु राज्य और अन्न।, 442 1993 का एच श्री सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी (विनियमित) और अन्य।वी.कर्नाटक राज्य और एस. एच. मुसलियार बनाम

केरल राज्य

655

ओआरएस।, 525 1993 डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति और अन्य।वी.हरियाणा राज्य और अन्य।, 469 1993 जेप्पियार एजुकेशनल ट्रस्ट एंड अन्न।वी.तमिलनाडु राज्य, और 1993 का 392 (भाषाई और धार्मिक संघ)

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, पुणे बनाम महाराष्ट्र राज्य) (हालांकि,

जैसा कि हम वर्तमान में कुछ याचिकाकर्ताओं को इंगित करेंगे-संस्थान प्रथम दृष्टया M.E.Is प्रतीत नहीं होते हैं। जिसमें हमने मामलों को स्थगित कर दिया है।हम.

/

उन्हें थोड़ी देर बाद निर्दिष्ट करेंगे)।चौथी श्रेणी में डब्ल्यू. पी. संख्या शामिल है।407/93 (मराठवाड़ा

मित्र मंडल बनाम।महाराष्ट्र राज्य, 399/93 कोल्हापुर प्रौद्योगिकी संस्थान v.महाराष्ट्र राज्य, 571/93 कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बनाम.भारत संघ, और 626/93 हैदराबाद (सिंध) राष्ट्रीय कॉलेजिएट बोर्ड और अन्य।वी.एस.

महाराष्ट्र राज्य और अन्य।इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता M.E.I.s होने का दावा नहीं करते हैं।चूँकि हम आज उनके मामलों पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मामलों को सामान्य रूप से पोस्ट करने के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

" हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड द्वारा दायर 1993 की रिट याचिका संख्या 626 जिसे श्रेणी (4) (अर्थात रिट डी) में दिखाया गया है।

उन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दायर किए गए उन्नीक शिक्षण की शुद्धता और प्रयोज्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित श्रेणी संख्या (2) में रखा गया है जो सहायता के रूप में राज्य निधि प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण भारत के मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन द्वारा दायर 1993 की रिट याचिका संख्या 597, जिसे श्रेणी संख्या (3) (यानी <आई. डी. 1) में रखा गया है, जिसके संबंध में रिट याचिकाओं में किए गए कथन से यह स्पष्ट नहीं है कि वे सहायता प्राप्त हैं या गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार उन्हें श्रेणी संख्या (1) में रखा गया है।

एफ पाँचवीं श्रेणी में एस. एल. पी. शामिल है। (ग) 1993 का 18890 (डॉ. बी. एम. थिप्पेस्वामी मेमोरियल एजुकेशनल एसोसिएशन बनाम।कामाकाता राज्य और

एन. आर.और 1993 का 463 टी. एम. टी. कन्नम्मल शिक्षा न्यास बनाम।तमिलनाडु राज्य और अन्य।

जहाँ तक डब्ल्यू. पी. 350/93 और 355/93 का संबंध है, इस न्यायालय के पास जी है।

याचिकाकर्ताओं की सहमति से 14 मई, 1993 को पहले ही आदेश पारित किए जा चुके हैं।हम उनके मामलों में उक्त आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।तथापि, उक्त आदेश (दिनांक 14 मई, 1993) इसके बाद उल्लिखित संशोधनों के अधीन होगा।

अब हम 1993 की रिट याचिका 284 और 1993 की 350 एच. सुप्रीम न्यायालय रिपोर्ट [1993] एस. पी. पर विचार करेंगे।

1 एस सी आर।

656

ए जो पूरी तरह से एक अलग पायदान पर खड़ा प्रतीत होता है।डब्ल्यू. पी. 284/93 में याचिकाकर्ता कर्नाटक में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कैथोलिक समुदाय द्वारा स्थापित एम. ई. आई. होने का दावा करता है।याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि वह कर्नाटक राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज चलाता है, कि वे किसी भी छात्र से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेते हैं, कि इन संस्थानों में उनके द्वारा ली जाने वाली शुल्क सरकारी कॉलेजों में ली जाने वाली शुल्क बी (और कुछ मामलों में उससे कम) से अधिक नहीं है और उनके संस्थानों में प्रवेश याचिकाकर्ता द्वारा अलग से आयोजित अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रवेश उक्त परीक्षा में निर्धारित योग्यता के आधार पर किए जाते हैं।यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के संस्थान अच्छी तरह से स्थापित संस्थान हैं और उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, हर साल हजारों छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और उपस्थित होते हैं।कर्नाटक राज्य के विद्वान महाधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं, हालांकि हमें दर्ज करना चाहिए, इस मामले में अभी तक कोई प्रतिवाद दायर नहीं किया गया है।उन्होंने इस बात पर भी विवाद नहीं किया कि याचिकाकर्ता द्वारा संचालित किसी भी कॉलेज के खिलाफ किसी भी समय अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली थी।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि 24 मई, 1993 के आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की है और चयन की प्रक्रिया व्यापक है।जो किया जाना बाकी है वह उन छात्रों को प्रवेश देना है जो उपरोक्त आदेश को देखते हुए नहीं किए गए थे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कपिल सिब्बल ने भी कुछ कानूनी दलीलें प्रस्तुत कीं जिन पर इस स्तर पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

W. P. 482/93 में याचिकाकर्ता वेल्लोर में एक मेडिकल कॉलेज चलाता है।

तमिलनाडु राज्य।याचिकाकर्ता के अनुसार, यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसमें प्रवेश याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है।यह कहा गया है कि प्रवेश योग्यता के आधार पर किए जाते हैं।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कॉलेज कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेता है, कि इसके द्वारा लिया जाने वाला शुल्क समान सरकारी संस्थानों में लिए जाने वाले शुल्क से अधिक नहीं है और

याचिकाकर्ता-संस्था के कामकाज के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं हुई है।श्री सीतारमन, तमिलनाडु राज्य के विद्वान वकील नहीं हैं

/

उपरोक्त कथनों पर विवाद करें।हालांकि हम फिर से दर्ज कर सकते हैं कि मामले में अभी तक कोई काउंटर दायर नहीं किया गया है।श्री साल्वे द्वारा याचिकाकर्ता के लिए प्रस्तुत किया गया है कि छुट्टियों के दौरान, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस रिट याचिका में एक अंतरिम आदेश दिया है जिसमें तमिलनाडु राज्य को याचिकाकर्ता द्वारा चयन नहीं किए गए प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता-संस्थान को कोई सीट आवंटित नहीं करने का निर्देश दिया गया है।याचिकाकर्ता के वकील श्री एच साल्वे ने आगे कहा कि प्रक्रिया 657

एस. एच. मुसलियार बनामकेरल राज्य

प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हालांकि इस न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रवेश ए नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर और उसी आधार पर छात्रों को अपने कॉलेजों में प्रवेश देने की अनुमति देते हैं।

उनके द्वारा पिछले शैक्षणिक वर्ष में उक्त कॉलेजों में प्रवेश दिए गए थे।प्रवेश पूरा करने के बाद, याचिकाकर्ता प्रवेश प्राप्त छात्रों, श्रेणियों, यदि कोई हो, जिसके तहत उन्हें प्रवेश दिया गया था और उनके प्रवेश से संबंधित अन्य सभी विवरणों का पूरा विवरण देंगे।यह जानकारी सक्षम लोगों को दी जानी चाहिए।

प्राधिकरण, उस विश्वविद्यालय के लिए जिससे उक्त कॉलेज संबद्ध हैं और सचिव, शिक्षा विभाग, कर्नाटक/तमिलनाडु सरकार के लिए।उक्त अधिकारी यह सत्यापित करेंगे कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश किए गए हैं। अनियमितता के मामले में, उक्त अधिकारियों में से कोई भी याचिकाकर्ता को उक्त अनियमितता को सुधारने के लिए बुलाने का हकदार होगा।सक्षम प्राधिकारी, विश्वविद्यालय और कर्नाटक/तमिलनाडु सरकार के लिए यह भी खुला रहेगा कि वे इस तरह की किसी भी अनियमितता को इस न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए उस ओर से उचित आदेशों के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से लाएँ।यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें दिए गए निर्देशों का कोई भी उल्लंघन

याचिकाकर्ताओं को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे क्योंकि उपरोक्त आदेश उनके अभ्यावेदन के आधार पर और उनके द्वारा व्यक्त की गई तात्कालिकता को देखते हुए संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा जवाबी शपथपत्र दायर किए जाने से पहले भी दिए गए हैं।

अन्य सभी मामलों में, इसके बाद विशेष रूप से उल्लिखित मामलों को छोड़कर, इस न्यायालय द्वारा 14 मई, 1993 को डब्ल्यू. पी. 355/93 और 350/93 में दिया गया आदेश निम्नलिखित एफ. संशोधनों के साथ होगा (जो संशोधन डब्ल्यू. पी. के मामलों में भी लागू होंगे)।

350/93 और 1993 का 355)।उक्त आदेश की निरंतरता में परिच्छेद 5,6 और 7 के रूप में क्रमांकित संशोधन निम्नलिखित हैं:

" (5) पैरा (3) की निरंतरता में यह और स्पष्ट किया गया है कि क्या जी याचिकाकर्ता-संस्थानों में से कोई भी एम. ई. आई. है या नहीं, यह मामला है -

सरकार का सत्यापन और निर्धारण करना।हम विशेष रूप से इस स्तर पर उस संबंध में कोई घोषणा नहीं करते हैं।यह आदेश केवल उन संस्थानों पर लागू होगा जो M.E.Is पाए जाते हैं।

सरकार द्वारा सत्यापन और उन लोगों के लिए नहीं जो इस तरह के सत्यापन पर M.E.Is नहीं पाए जाते हैं।

एच 658

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1993] एस. यू. पी.1 एस सी आर।

(6) राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्धी परीक्षा/परीक्षा के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली 50 प्रतिशत सीटें और साथ ही उक्त आदेश के पैरा (2) के खंड (ii) के अनुसार भरी जाने वाली शेष 50 प्रतिशत सीटें निशुल्क सीटों और भुगतान सीटों के बीच समान रूप से वितरित की जाएंगी।दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा भरी जाने वाली 50 प्रतिशत सीटों में से आधी भुगतान की सीटें होंगी और आधी निशुल्क सीटें होंगी।इसी तरह, उक्त आदेश के पैरा 2 (ii) के अनुसार प्रबंधक द्वारा भरी जाने वाली 50 प्रतिशत सीटों में से आधी भुगतान की सीटें होंगी और आधी निशुल्क सीटें होंगी।अंतर्गत डी. 1.....।

/

/

/

प्रवेश पूरा करने के बाद प्रत्येक कॉलेज सक्षम प्राधिकारी को, उस विश्वविद्यालय को, जिससे वह संबद्ध है और इस आदेश के पैरा (ii) के खंड (2) के अंतर्गत भर्ती किए गए छात्रों के पूर्ण विवरण वाले संबंधित सरकारी विवरणों को प्रस्तुत करेगा।इस तरह की स्थिति में यथासंभव पूर्ण विवरण शामिल होंगे।जिन अधिकारियों ने डी को बयान प्रस्तुत किए हैं, वे बयानों की शुद्धता की पुष्टि करेंगे और यदि उन्हें कोई अनियमितता मिलती है, तो वे संबंधित कॉलेज से इसे सुधारने के लिए कहेंगे।वे एक अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से इस तरह के किसी भी उल्लंघन को इस न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे।अगर ऐसी कोई अनियमितता साबित हो जाती है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

/

14 मई, 1993 का आदेश डब्ल्यू. पी. 479/93 तमिलनाडु तकनीकी शिक्षा फाउंडेशन, डब्ल्यू. पी. 597/93 (मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया), डब्ल्यू. पी. 442/93 श्री सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य रिट याचिकाओं में संबंधित संस्थानों पर लागू नहीं होगा।वी.कर्नाटक राज्य, डब्ल्यू. पी. 525/93 डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति बनामएफ हरियाणा राज्य और डब्ल्यू. पी. 392/93 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान संघ, पुणे बनाम।महाराष्ट्र राज्य, क्योंकि हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हैं कि उन्हें M.E.Is के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। इन याचिकाओं को 22 सितंबर, 1993 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।14 मई, 1993 का आदेश चौथी और पांचवीं श्रेणियों में उल्लिखित रिट याचिकाओं पर भी लागू नहीं होगा।

/

हम उल्लेख कर सकते हैं कि डब्ल्यू. पी. 598/93 में, श्री एफ. एस. नरीमन ने संस्थान और केरल सरकार के बीच हुए एक निश्चित समझौते की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके अनुसार 85 प्रतिशत सीटें सरकार द्वारा भरी जानी थीं, जबकि शेष 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन को अपने विवेक से भरने के लिए छोड़ दी गई थीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त एस. एच. मुसलियार बनाम।

केरल राज्य

659

वर्तमान शैक्षणिक एक वर्ष के लिए भी समझौते को लागू करने की अनुज्ञात जा सकती है।चूँकि उन्नीकृष्णन में मूल सिद्धांत के साथ-साथ यहाँ दिए गए आदेश यह हैं कि योग्यता प्रवेश के मामले में मार्गदर्शक सिद्धांत होगी, इसलिए हम विवेकाधीन कोटा के लिए याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते।उक्त रिट याचिकाएं भी उपरोक्त संशोधनों के साथ 14 मई, 1993 के आदेश द्वारा शासित होंगी।

/

जहाँ तक एसएलपी 12898/93 का संबंध है, हम कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करते हैं और मामले (पहले से ही अलग से पारित आदेश) से निपटने के लिए इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देते हैं।यह उल्लेख किया जा सकता है कि उक्त एस. एल. पी. को एक रिट याचिका लंबित रहने तक एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है।डब्ल्यू. पी. 463/93 में याचिकाकर्ता एक धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का दावा करता है लेकिन सी यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह कैसे और किस तरीके से है।यह नहीं बताया गया है कि किस विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक ने उक्त संस्था की स्थापना की है और इसे प्रशासित किया है।तदनुसार रिट याचिका को 22 सितंबर, 1993 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जहाँ तक 1993 की रिट याचिका संख्या 317 का संबंध है, वर्तमान समय में कोई आदेश पारित नहीं किए जाते हैं।भारत संघ द्वारा दायर 1993 का आई. ए. सं. 3 अभियोग आवेदन अनुज्ञात है।22 सितंबर, 1993 को पोस्ट करें।हमारी राय है कि एक बड़ी पीठ को इस प्रश्न की सुनवाई करनी चाहिए।

मामलों की इन पीठों में उत्पन्न होने वाले मामले।हम, निश्चित रूप से, संकेत देंगे कि 22 सितंबर, 1993 को बड़ी पीठ द्वारा किस पर सुनवाई की जाएगी।

हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उपरोक्त आदेश रिट याचिकाओं में पक्षों के अधिकारों और विवाद और आगे के अंतर्वर्ती आदेशों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पारित किए जाते हैं जो इसके बाद पारित किए जा सकते हैं।

/

सुनवाई की अगली तारीख के भीतर कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें (इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त समितियों के माध्यम से) उनके द्वारा अधिसूचित शुल्क संरचना पर फिर से विचार करेंगी।याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला रहेगा कि वे सरकारों के समक्ष ऐसी सामग्री रख सकें जो वे इस संबंध में उचित समझते हैं।सरकारें ऐसी सामग्री या ऐसी अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकती हैं जो उनके पास हो।निपटाई गई याचिकाएँ।

एजी.